RAJYA SABHA

Tuesday, the 5th March, 1991/the 14th Phalguna, 1912 (Saka)

The House met at two minutes past eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

RE. THE STATEMENT PROPOSED TO BE MADE BY PRIME MINISTER ON THE QUESTION OF SURVEILLANCE

MR. CHAIRMAN: Question No. 121.

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat): Mr. Chairman, Sir, our party is seriously exercised on the question of surveillance and the Deputy Chairman was pleased to announce yesterday that the Prime Minister would be pleased to make his observations or statement today. The Prime Minister is here. May we expect it from the Prime Minister, Sir?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): Sir, all of us demand that there should be a statement.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, all of us are equally exercised, and yesterday we could make our point because the business of the House was brought to a stand-still.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Sir, we should be allowed to say something on that before the Prime Minister makes the statement.

श्री अटल विहारी वाजपेयी : (मध्य प्रदेश) : नहीं, नहीं स्टेटमेंट सुनने के बाद . (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Deputy Chairman said that you have promised to make a statement at 12 o'clock...

THE PRIME MINISTER (SHRI CHANDRA SHEKHAR): As you like. I am in your hands, Mr. Chairman.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He is going to make a statement at 12 o'clock. *(Interruptions)*

श्री अटल विहारी वाजपेयी : प्रश्नों के बाद ।

श्री सभापति : प्रश्नों के बाद । बारह बजे कह रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर हमें स्पष्टीकरण पूछने का अवसर मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : वह देखा जायेगा कि वह क्या कहते हैं । स्पष्टीकरण आवश्यक हैं कि नहीं । . . . (व्यवधान)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब में उग्रवाद से निपटने के लिए कार्रवाई

*121. श्री हरवंश सिंह हंसपाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब प्रशासन उस राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिये एक सुनियोजित कार्रवाई आरम्भ करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कदम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब में इस वर्ष जनवरी से उग्रवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों के द्वारा पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियों को किस हद तक रोने जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख)

समस्या का एक दीर्घकालीन हल खोजने के लिये एक संपूर्ण सुनियोजित नीति के एक भाग के रूप में, पंजाब सरकार ने लोगों की जान और माल की रक्षा करने के उद्देश्य से कई उपाय किये हैं जिनमें प्रशासन को कारगर बनाना तथा लोगों में विश्वास पैदा करना तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त करना शामिल है । इसी नीति को अपनाते हुये, 20 फरवरी से 14 मार्च, 1991, छह हफ्ते तक चलने वाला एक लोक जागृति अभियान भी चलाया गया है ।

(ग) जी नहीं श्रीमन ।

(घ) आशा की जाती है कि किए गये उपायों से स्थिति में सुधार आयेगा ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : चेयरमैन महोदय, मेरा क्वेचन था कि whether Punjab administration propose to launch a planned operation to counteract militancy in the State. और उसका जवाब अगर यह आ जाए तो वह काफी था, मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया, ठीक है, लेकिन 'बी" पार्ट में मैंने पूछा था : if so, the details of the proposed steps.

और वह डिटेल बिल्कुल इसमें बताई नहीं गई हैं । 10 फरवरी के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में जो रिपोर्ट हुआ है, 9 तारीख की खबर में, कि पंजाब के गवर्नर जनरल ओ० पी० मल्होत्रा ने यह कहा कि the administration will shortly launch a planned operation to counteract militancy in the State.

मैं इसके लिये जानना चाहूंगा कि वह प्लांड आपरेशन क्या है या वह क्या था, वह आपरेशन चालू किया गया या नहीं किया गया ? अगर किया गया तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति महोदय, जो पूरे अभियान वहां पर शुरू किये गये हैं वह एक अभियान तो है कि जो इलाके सबसे ज्यादा आतंकवादियों की गतिविधियों से प्रभावित थे उन इलाकों को पूरी तरह से सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा सुरक्षित करना और आज के दिन मैं यह कह सकता हूं कि दो-तीन जिले जो सबसे ज्यादा जैसे फिरोजपुर, अमृतसर इन सब इलाके में हमारे पैरा-मिलिट्री फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है, वहां पर रात में गश्त पूरी तरह से शुरू की गई है, ज्यादा संख्या में पिकेट्स लगाई गई है, विलेज के डिफेंस के लिये लोगों को मोबिलाइज किया गया है और उससे ज्यादा जो विल एड-मिनिस्ट्रेशन के लोगों को अप टू पंचायत स्तर तक इन्वाल्व किया गया है और पंचायत से गांव के लोगों को चाहे वह सरपंच हो, चाहे जो भी वहां के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों का जैसे पार्टिसिपेशन हो वह भी उसी कार्यक्रम के तहत शामिल है । जैसे कि मैंने बताया कि जो वहां पर पीस मार्च और जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है उसकी बहुत अच्छी संभावनायें नजर आ रही है और एक सेंस आफ कंफीडेंस वहां के लोगों में पैदा हुआ है । जो हम लोगों के पास फिगर है अभी, उनसे लगता है कि वहां स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है मैं क्लेम नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस दो-तीन महीनों में वहां एक सुधार का सिग्नल हम लोगों को मिल रहा है ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : चैयरमैन महोदय, मंत्री महोदय ने कुछ बातें कहीं, ठीक है, ऐसा हुआ होगा उन तीन जिलों में, लेकिन बाकी जिलों में क्या हो रहा है वह मंत्री महोदय ने नहीं बताया । जितनी किलिंग उन तीन जिलों में बन्द हुई है उससे कहीं ज्यादा दूसरे जिलों में हो रही है, खास तौर से पटियाला और लुधियाना में, वहां पर पहले से ज्यादा आतंकवाद फैल हुआ है । उसका नमूना यह है कि वहां से 20 लोगों को उठा लिया गया और जब उनको छुड़वाने के लिये वहां पर गवर्नर ने जाना था तो गवर्नर को मारने की साजिश वहां पर बनाई गई । इसी तरह से वह लोग,

गवर्नर वहां नहीं पहुंचे तो डी.जी.पी. मांगट पहुंचे और उनके ऊपर किस तरह से प्लानिंग करके उन्होंने टार्गेट से बूलेट प्रूफ गाड़ी को उड़ा दिया। कैसे ही वह बच तो गये लेकिन उनके साथ उनके सेक्रेटरी मि सेठी बैठे हुये थे उनकी एक टांग उड़ गई। इतनी प्लानिंग से, इतनी बारीकी से काम किया, रिमोट कंट्रोल से वहां पर यह काम हुआ। मेरे कहने का भाव यह है कि अगर वहां पर आपको कुछ सफलता मिली भी है तो दूसरी जगह पर उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी से खास तौर से यह जानना चाहूंगा कि जब यह इनकी सरकार आई तो मझे ऐसा लगा कि जैसे पिछली सरकार ने भी पंजाब को प्रायरिटी पर लिया प्रधान मंत्री जी ने यह पंजाब के इश्यू को प्रायरिटी दी और इन्होंने मि मान से बात-चीत की, बहुत से लोगों, बहुत सी पार्टियों ने उसका विरोध किया, लेकिन मैंने और मेरे कुछ एम०पीज़ और कुछ एक्स एम०पीज़ ने पंजाब से, बावजूद आपके बात-चीत की खिलाफत की हमारी पार्टी के अन्दर भी हमने उसका सपोर्ट किया ओपनली और प्रैस में स्टेटमेंट दिये ताकि आप इस बात से एनकरेज हों और इस बात को किसी सिरे पर चढ़ायें। लेकिन मैं यह जानता हूं कि उसके बाद आप भी, अगर वह सब कह दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, पंजाब के बारे में आप भी सो गये।

श्री सभापति : आप प्रश्न करके जगा दीजिये।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मान साहब ने जिनके साथ यह बात कर रहे थे या करना चाहते थे यह तो इनको मालूम होगा, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिये हैं जिसके ऊपर सरकार ने कोई काम या कोई एक्शन आज तक नहीं लिया, लेकिन जो अखबार उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर प्रैस सेंसरशिप तो नहीं लगी है, लेकिन उन अखबारों में क्या दुर्गति की जा रही है। यह आपको भली प्रकार मालूम होगा। यह रोज प्रेस में आ रहा है। एक तरफ तो आप उनसे बात करना चाहते हैं। वह इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, उन पर आप कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन जो अखबार उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर आप एक्शन ले रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने वहां पर मिलिटरी नहीं भेजी, मिलिटरी वहां एक्सरसाइज के लिये गयी थी। वह हमने मान लिया। लेकिन मिलिटरी के लोगों ने 6 आदमियों को मार दिया। तो यह सब वहां पर क्यों हो रहा है? मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप वहां पर कोई एक्शन लेने जा रहे हैं या नहीं? अगर लेने जा रहे हैं तो वह क्या एक्शन है? मैं इससे आगे जाऊं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं ... **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : अगर जाना चाहते हो तो जाइये, हमें कुछ नहीं छिपाना।

श्री सभापति : यह कोई डिबेट नहीं हो रही है। आपका प्रश्न तो हो गया। जवाब दीजिये।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री चन्द्रशेखर : मैं सभापति जी, दो-एक बातें बहुत साफ कर देना चाहता हूं। समस्या मैंने शुरू नहीं की, जब यह सरकार आई तो समस्या थी। मैंने मान साहब या किसी व्यक्ति विशेष से बात करने की बात नहीं कही। हमने कहा कि पंजाब या जो दूसरे मामले झगड़े के हैं, उसमें हर किसी से हम बात करने को तैयार हैं। मान साहब आये, उनसे मैंने बात की। मान साहब फिर आने वाले थे, वह नहीं आये। इसलिये उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई, न हमारी उनसे कोई बात चल रही है। जहां तक किसी प्लान का सवाल है, सरकार कहां, कब, कौनसी

पुलिस भेजेंगी, कहां पर मिलिटरी का इस्तेमाल होगा, किस तरह से पैरा-मिलिटरी आर्गनायजेशंस काम करेंगे, यह विवरण देना मेरे लिये संभव नहीं है, क्योंकि वह मुझे भी नहीं मालूम । लेकिन मैंने मान से भी कहा था, इस सदन में भी कहा था और फिर मैं आज दोहराता हूं, मैंने प्रारंभ में कहा था कि जब कोई बातचीत होगी तो पहली शर्त यह होगी कि मौत का माहौल वहां बन्द हो और मैंने कहा था सरकार की ओर से कोई अत्याचार का काम नहीं होगा जैसी कि उनकी शिकायत थी । लेकिन अगर निर्दोष लोग मारे जायेंगे तो सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी और पुलिस उसको पूरी सख्ती से रोकने की कोशिश करेगी । वही नीति आज भी है ।

जहां तक हमारे माननीय मित्र ने बताया, तीन जिलों में जब दबाव पड़ा तो यह सही बात है, माननीय सदस्य ने कहा कि वह लोग मालवा की तरफ से आये, पटियाला और दूसरी जगहों पर उन्होंने कुछ लोगों के साथ अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण काम किया । लेकिन इसके साथ-ही-साथ जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़ शहरों में स्थिति में सुधार हुआ है । पटियाला में भी स्थिति में सुधार हुआ है । अब जो संख्या है, वह तो बदली नहीं जा सकती । यह जरूर हो रहा है कि जहां तक आतंकवाद हो रहा है वहां हमारे पैरा मिलिटरी आर्गनायजेशंस और पुलिस के लोग वहां पर जाते हैं और उसकी वजह से एक दूसरे से मुठभेड़ हो रही है । सभापति जी, यह पहली बार हुआ है कि जब कोई आतंकवादी मरता है तो हम यह नहीं कहते कि दुर्दांत आतंकवादी मारा गया । हम उसका नाम बताते हैं । ये वह लोग हैं, जो वांछेड लिस्ट में हैं । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हर एनकाउंटर में या तो हमारी पुलिस का जवान घायल होता है या कई जगह मरता है । इस लिये हम पुराने तरीके तो नहीं अपना रहे हैं कि निर्दोष लोगों को पकड़कर मार दें । लेकिन अगर मौत का माहौल दूसरी ओर से चल रहा है तो हम ऐसा मानते हैं कि पुलिस और पैरा-मिलिटरी आर्गनायजेशंस पूरी ताकत से उसको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है ।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं और उनके जरिये सदन को कि सरकार सोई हुई नहीं है । लेकिन अखबारों में भाषण देकर के सरकार नहीं जगी हुई है । सरकार के जो अंग हैं—पैरा मिलिटरी आर्गनायजेशंस, वे वहां गांवों की गलियों में रात में और दिन में जगे हुये हैं और स्थिति हमारे लिये संतोषजनक नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे नियंत्रण में आ रही है ।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : महोदय, मान साहब का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है और आर्मी भेजने के बारे में प्रधान मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा । मान साहब का आनन्दपुर साहिब में जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री चन्द्रशेखर : सभापति जी, मान साहब के किसी वक्तव्य को मैं सार्थक वक्तव्य नहीं मानता । यदि मान साहब कोई ऐसा वक्तव्य देंगे जिस वक्तव्य से देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई मुश्किल पैदा होगी तो उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और यदि कोई समाचार-पत्र इस तरह के वक्तव्यों को प्रकाशित करेंगे तो मुझे विवश होकर कभी-कभी यह निर्देश देना पड़ता है कि ऐसे समाचार-पत्रों का सर्कुलेशन रोक दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से कहना चाहता हूं कि मान साहब के हर वक्तव्य का जवाब देना सरकार उचित नहीं समझती और न उसको इतना महत्व देती है कि उनके हर वक्तव्य का हम जवाब दें और आर्मी भेजने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है । यह बात सही है कि आर्मी वहां पर रेगुलर वे में, जैसे सारे देश में मौजूद है, वहां भी मौजूद है । अगर कहीं स्थिति गड़बड़ होगी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने यह कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो आर्मी का इस्तेमाल करेंगे । लेकिन आर्मी के आपरेशन की कोई योजना नहीं है ।

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, I would like to refer to the Prime Minister's reply just given, I think he has made a strange and objectionable comment, when he said that the present Government is not following the policy of the earlier Government of arresting the innocent people and killing them. I think it will create a serious problem in Punjab. (*Interruptions*).

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Mr. Chairman, I said that now there is no news in the Press that such and such dreaded terrorists "were killed". I said that if a terrorist is killed, his name is given. I said that there is no complaint that there are any fake encounters.

SHRI SUKOMAL SEN: What he has said is on record.

MR. CHAIRMAN: Let us go by what he has said.

SHRI SUKOMAL SEN: The point is that there are two ways of counteracting with the militants in Punjab. One is the law and order machinery and the other is the political machinery. Now after Shri Chandra Shekhar came into power as the Prime Minister, he took initiatives to talk with Mr. Mann and he had made an open appeal to the terrorists to come for a dialogue. Now, I would like to know as to what is the impression of the Government after his talk with Mr. Mann and after his open appeal for a dialogue with the militants. Has it improved the situation to any extent in Punjab, or has it been considered by the militants as the weakness of the Government? I would like to know whether it is a fact that after his talks with Mr. Mann and his appeal to the terrorists, the killing of innocent people has further increased.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Mr. Chairman, Sir, the fact is that the killings have not increased. There was a period when there were lots of killings. Now, it has gone down. It is very difficult to analyse the psychology of the terrorists because we are not in touch with them. But the psychology of the people in Punjab has been of a healthy nature because of our offer of talks.

People feel that the Government is doing everything possible. If they are not coming forward for a negotiated settlement, the fault is theirs. We have to win over the mind of the people not specially the mind of the terrorist.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो फ्लड आफ-रेशन की बात कही जाती है पंजाब में, इसके एक विषय के बारे में, काफी समय से सरकार यह कहती चली आ रही है कि सीमा पर हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा-पट्टे के द्वारा हमारा सुझाव है, लेकिन सीमा को पूरा सील करने के लिए ग्रफट्स होने चाहिएं, इसके बारे में समय-समय पर कहने के बावजूद भी फेंसिंग के कार्य में जो गति होनी चाहिए, वह नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने किलोमीटर सीमा सील हो चुकी है, अर्थात सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है और कितने पर फ्लड-लाइट लग चुकी है। इस बारे में कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि यह सारा काम कब तक कंपलीट हो जाएगा?

श्री सुबोध कान्त सहाय : सभापति जी, हम लोगों ने यह मार्च का टारगेट दिया है, लेकिन मार्च के टारगेट तक लगता नहीं कि यह कंपलीट कर पाएंगे। हकीकत है कि सी०पी० डब्ल्यू०डी० और सरकार की प्राथमिकता यही है कि वहां पर बोर्डर फेंसिंग का काम और फ्लड-लाइट का काम जो दूसरे फेज में आज है, उसको कंपलीट किया जाए। उसके बाद वहां रिवरेन एरिया है, जो नदी का इलाका है, वह सारा इलाका हम समझते हैं कि बच जाएगा। लेकिन यह प्राथमिकता के तहत है कि जिस तरह से हो हम वह काम पूरा करें। माननीय सदस्य, पहले और आज की स्थिति में

श्री सभापति : वह पूछ रहे हैं कि कितना हो गया और कितना बचा है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : करीबन आज जो है, वह 236 किलोमीटर तक के इलाके के लिए काम चल रहा है।

श्री सभापति : अभी हो कितना गया है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : हुआ है 120 किलोमीटर, पहले और उसके बाद का इलाका जो है, जो लगा हुआ है, उसमें काम हो रहा है।

श्री सभापति : 120 का हो गया और आगे का काम चल रहा है, 236 किलोमीटर में होना है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि मार्च तक के टारगेट में यह पूरा नहीं होगा। तो क्या कोई टारगेट अब तय हुआ है कि यह कब तक पूरा होगा ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने खुद ही वहां पर यह सीलिंग लगाया था कि मार्च तक काम पूरा करें। मैं समझता हूं कि बारिश से पहले वह काम उस इलाके में पूरा हो जाएगा।

SHRI S. B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, I would like to get a clarification from the Government on a very important matter which has been reported in the Press. First of all, the Government has been persistently saying that a neighbourning country, namely Pakistan, is giving full training, arms and other material to the militants. I am sure, unless there is another foreign power assisting Pakistan, it will not be able to go ahead with this kind of a plan. Recently, it has been reported in the Press that the Prime Minister of U.K. had stated publicly that his Government does not want to encourage any kind of terroism from Pakistan, in India. This is the kind of statement ascribed to the Prime Minister of U.K. I would like to know how far this is correct? Has the Government any information on this account?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Sir, it is true that there was a statement from the U.K. Government that they do no want to encourage any terrorist activities in Kashmir. It was about Kashmir and not about Punjab. But they said that they are against such terrorist activities. There is a proposal from the Government of U.K. They are coming out with an enactment to provide that all funds which are collected for aiding terrorist activities would be confiscated. We are discussing the matter with them and a decision would be taken soon.

SHRI S. JAIPAL REDDY: It was reported in the Press that our Prime Minister and the Prime Minister of Pakistan had both telephonic and personal contacts in regard to the terrorist activities in Punjab and in regard to the need for the Pakistan Government restraining such terrorist activities on their soil. I would like to know whether, since then, there has been any distinct improvement in the approach of the Pakistan Government towards this question?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: It is true that I had, twice or thrice, talks with the Prime Minister of Pakistan. He assured that his Government will not help in these terrorist activities. It is very difficult for me to say whether the present change is because of this co-operation, or, it is a natural happening, for the time being. We are hoping that the Government of Pakistan will co-operate with us because, it is in the interest of both the countries that we should have cordial and friendly relations. The Government of India is extending all co-operation to the Pakistan Government and we expect reciprocity from them.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Mr. Chairman, Sir, a few days ago, there was an item in the newspapers that an army unit had killed six villagers. I do not know what duty they were doing. There were a number of villagers travelling in a tonga. They were asked

to halt, but they felt frightened and started running. Six persons were killed. I am pointing this out because, in Punjab, there has been a great deal of hue and cry on this. There is an impression that the Army is being used against the so-called terrorists or militants and they do not believe what the Prime Minister has said, that it is not being used. I would like to seek a clarification as to how these six villagers were killed. If it was a question of stopping them, was it necessary to kill these unarmed persons? Or, were the army personnel trigger-happy?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Sir, unfortunately, there have been some incidents of ambush of army personnel, without any provocation. They are also under a severe strain. It is true that six persons were killed. An initial enquiry indicated that they were innocent. The army authorities themselves have taken up this matter. They are investigating and they are going to take measures against those who were responsible for this type of killing. But what the hon. Member said is correct that there is strain sometimes. He has been leader of army for quite some time. If they are ambushed without any provocation, sometimes some people under the apprehension do things which are perhaps not required, but the matter is being investigated by army authorities and proper and suitable action will be taken in the matter.

Report of National Commission on SCs/STs

*122. DR. JINENDRA KUMAR JAIN:†

SHRI BAL RAM SINGH YADAVA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in its report submitted to Government, has urged that special courts be set up in every State in order to settle on time the outstanding cases of atrocities committed on Harijans and Girijans;

(b) if so, which are those States where such special courts could not be set up till December, 1990;

(c) whether Government will take effective steps for establishing such courts in all States in future; and

(d) if so, by when Government propose to set up such courts in every State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI RAMJILAL SUMAN): (a) The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Report on 'Atrocities on Scheduled Castes and and Tribes: Causes & Remedies' has *inter-alia* observed/recommended 'designating existing sessions courts as special courts under the Prevention of Atrocities Act will not ensure priority attention for atrocity cases. There should be special courts exclusively for atrocity cases. Where the number of atrocity cases in a District does not provide adequate workload there should be itinerating Special Courts covering two or more districts invested with the powers of additional special courts for each of the District.'

(b) to (d) All States and Union Territories, except Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland have specified Special Courts as required under Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. However, the Government have been pursuing with States/Union Territories for setting up of even exclusive Special Courts. So far only the State of Rajasthan has set up six exclusive Special Courts for trying atrocity cases against SCs and STs.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Mr. Chairman, Sir, there has been no dearth of legislative provisions and availability of Commissions and committees to promote or at least to protect the interest or

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Jinendra Kumar Jain.